

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयाँकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुनर्वास निदेशक,
टिहरी बाँध परियोजना,
नई टिहरी।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक: 15 जनवरी, 2016

विषय- जनपद टिहरी गढ़वाल में भल्लियाणा-मोटणा रोपवे निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, क्षेत्राका, लोक निर्माण विभाग, टिहरी के पत्र संख्या-101/मु0अभि0/याता-2015 दिनांक 22 जून, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल में भल्लियाणा-मोटणा रोपवे निर्माण कार्य का पुनरीक्षित विस्तृत आगणन स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य की मूल स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता (पुनर्वास), टिहरी बाँध परियोजना के पत्र संख्या-11/SE(R)/DD/Estimate दिनांक 06-12-2005 के द्वारा ₹ 215.00 लाख हेतु प्रदान की गई। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मोनो केबल कार एवं रोपवे का निर्माण, स्थल विकास, भूमि अधिग्रहण, सर्वे, मृदा परीक्षण तथा कन्सलटेंसी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त रोपवे के निर्माण में टिकट कक्ष, शौचालय, यात्री शेड तथा स्टोर आदि के लिये भवन निर्माण तथा आन्तरिक विद्युतीकरण, अग्निशमन व्यवस्था, तड़ित चालक व्यवस्था, सर्विस कनेक्शन, वाह्य विद्युतीकरण, जलापूर्ति, सम्पर्क मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं दो वर्ष तक रोपवे संचालन हेतु संचालन शुल्क एवं कन्टीजेंसी आदि कार्य किये जाने अवशेष है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 215.00 लाख में अवशेष कार्यों का निर्माण कार्य पूर्ण न हो पाने तथा इस क्रम में आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की अध्यक्षता में दिनांक 17-01-2015 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, टिहरी द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन, जिसकी विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई सम्पूर्ण लागत ₹ 461.00 लाख (₹ 215.00 लाख पूर्व स्वीकृत लागत + ₹ 246.00 लाख पुनरीक्षित लागत) है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय किये जाने की, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

6- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जायेगा।

8- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

- 9- स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- 10- पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं का होगा।
- 11- उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही पुनरीक्षित लागत ₹ 461.00 लाख (₹ 215.00 लाख पूर्व स्वीकृत लागत + ₹ 246.00 लाख पुनरीक्षित लागत) का वित्त पोषण पुनर्वास निदेशालय के माध्यम से टी0एच0डी0सी द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि से किया जायेगा।
- 12- यह आदेश सिंचाई विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
अपर सचिव।

संख्या:- 230 (1)/111(2)/16-35(प्रा0आ0)/2015 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी टिहरी।
4. प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग टिहरी।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/टिहरी।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, टिहरी।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0पांगती)
उप सचिव